संख्याः 18³²/XVII-3/2017-07(22)/2009

प्रेषक,

कै0 आलोक शेखर तिवारी, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

21 नवम्बार, 2017 देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2017

विषय:--एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत स्थापित आई०टी० इनैबल्ड सैल हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—748/नि.अ.क./ITCell-Budget/2017—18, दिनांक 13.09.2017, शासनादेश संख्याः 34/XVII-3/2017—07(22)/2009, दिनांक 03.02.2017 तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30.06.2017 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3/22/2008-UK-पी0पी0—I, दिनांक 23/26.12.2016 के द्वारा एम. एस.डी.पी. योजनान्तर्गत स्थापित आई.टी. इनैबल्ड सैल में कार्यरत कम्प्यूटर प्रोग्रामरों के वित्तीय वर्ष 2015—16 के लिम्बत मानदेय, स्टेशनरी, टेलीफोन तथा यात्रा व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 7,45,200/—के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 1,36,800/— (₹ एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ मात्र) को एम.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3/22/2008-UK-पी0पी0—I, दिनांक 23/26.12.2016 में दिये गये समस्त निर्देशों एवं एम0एस0डी0पी0 की गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2. उक्त स्वीकृत धनराशि का समायोजन भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में आई.टी. इनैबल्ड सेल हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि से किया जायेगा।
- 3. यदि उक्त कार्मिकों को भारत सरकार से स्वीकृति की प्रत्याशा में विभाग की अन्य योजनाओं से धनराशि की भुगतान किया गया हो, तो सर्वप्रथम उसका समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4. वित्त विभाग के उपरोक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तो एवं दिशा—िनर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जायेगा।
- 5. उक्त मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
- 6. आय—व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

- 7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
- 8. मितव्यययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 9. स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—15 'राजस्व' पक्ष के "लेखाशीर्षक—2250—अन्य सामाजिक सेवायें—00—01—केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना—0101— अल्पसंख्यकों हेतु मल्टी सेक्टोरल विकास योजना" के मानक मद 20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
- 3— यह आदेश शासनादेश सं० 183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बुजूट आवंटन हेतु निर्गत विषिश्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. सं० S + 11150 + 32, दिनांक 21-34 देखें के 2017 के अन्तर्गत तथा वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के द्वारा प्राप्त दिशानिर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(कैo आलोक शेखर तिवारी) अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः \832(1)/XVII-3/11-07(22)/09 तद्दिनांकित। प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषितः—

- 1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 3/22/2008-UK-पी0पी0—I, दिनांक 23/26.12.2016 के कम में I
- 3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4. जिलाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर।
- 6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 7. ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून / हरिद्वार / उधमसिंहनगर।
- निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9. नोडल अधिकारी, आई0टी0 इनेबल्ड सेल, देहरादून।
- 10. गार्ड फाइल।

(जी.एस. भाकुनी) उप सचिव।